

वैश्वीकरण और उदारीकरण का प्रभाव रोजगार उत्पादक और प्रतिस्पर्धात्मकता का एक अध्ययन मध्य प्रदेश राज्य के विशेष सन्दर्भ में

प्राप्ति: 026.08.2024

स्वीकृत: 18.09.2024

69

डॉ विद्यानंद पांडेय

अर्थशास्त्र विभाग,

शासकीय महाविद्यालय, लटेरी जनपद

विदिशा बरकतउल्ला विश्वद्यालय भोपाल

ईमेल: vnp1774@gmail.com

कुमारी ललिता यादव

शोधार्थी, भूगोल विभाग,

श्री देवी विश्वविद्यालय

टेहरी, उत्तराखण्ड

सारांश

यह अध्ययन रोजगार उत्पादक और प्रतिस्पर्धात्मकता पर ध्यान केंद्रित करते हुए मध्य प्रदेश में उद्योगों पर वैश्वीकरण के प्रभावों की जाँच करता है। मिश्रित तरीकों के दृष्टिकोण का उपयोग करते हुए मात्रात्मक और गुणात्मक डेटा को मिलाकर हमने क्षेत्र के विभिन्न उद्योगों पर वैश्वीकरण के प्रभाव का विश्लेषण किया हमारे निष्कर्ष बताते हैं कि वैश्वीकरण ने कुछ उद्योगों में प्रतिस्पर्धा उत्पादकता और नवाचार में वृद्धि की है जबकि अन्य ने अनुकूल के लिये संघर्ष किया है हमने यह भी पाया कि कुछ क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़े हैं। लेकिन नौकरी की सुरक्षा और मजदूरी में कमी आई है। अध्ययन में उन नीतियों की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया है जो क्षेत्र में प्रतिस्पर्धात्मकता और सतत विकास को बढ़ाने के लिये छोटे और मध्यम आकार के उद्यमों को कौशल विकास और नवाचार का समर्थन करती हैं यह शोध मध्य प्रदेश में उद्योगों पर वैश्वीकरण के प्रभाव को समझने में योगदान देता है। और नीति निर्माताओं और उद्योग हितधारकों के लिये अंतर्दृष्टि प्रदान करता है।

अनुसंधान ढांचा –

1. वैश्वीकरण ने मध्य प्रदेश में उद्योगों में रोजगार पैटर्न को कैसे प्रभावित किया है।
2. मध्य प्रदेश में उद्योगों में उत्पादकता और दक्षता पर वैश्वीकरण का क्या प्रभाव पड़ा है।
3. मध्य प्रदेश में उद्योगों में प्रतिस्पर्धात्मकता और नवाचार के मामले में वैश्वीकरण की चुनौतियों को कैसे अपनाया है ?

उद्देश्य:

1. मध्य प्रदेश में उद्योगों में रोजगार पर वैश्वीकरण के प्रभाव का विश्लेषण करना.
2. मध्य प्रदेश में उद्योगों में उत्पादकता और दक्षता पर वैश्वीकरण के प्रभाव की जांच करना
3. वैश्वीकरण की स्थिति में प्रतिस्पर्धात्मकता और नवाचार को बढ़ाने के लिए मध्य प्रदेश में उद्योगों द्वारा अपनाई गई रणनीतियों की जांच करना

1. साहित्य समीक्षा—डॉ सिंह मनमोहन: (Post Reform, Oxford Publication, New Delhi and London Press 2005 volume 2)

इस पुस्तक में भारतीय अर्थव्यवस्था की 1992 के पृष्ठभूमि को बड़ी रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारी से अवगत कराया है साथ ही साथ इसके फलीभूत होने और लागू होने के मान्यता को लेकर बारीकी से अध्ययन किया गया है।

2. डॉ भरत झुनझुनवाला:

भारत की अर्थनीति राजपाल प्रकाशन दिल्ली में उदारीकरण के कारण विदेशी निवेश और उद्योगों के विकास के लिए जोखिम उठाने की क्षमता को मजबूत करने के लिए तैयार प्रश्नों को हल करने के लिए भारत के अतीत में अनुभवों बहुत ही बारीकी से जानकारी दी गई है विकल्प देशी अदांज में और अधिक तकनीकी विकास को बढ़ावा देने के लिए सुझाव दिया है।

3. डॉ सेन अमर्त्य:

बंगाल और अकाल के माध्यम से पीपी को महत्व देकर उदारीकरण के बाद इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में समस्या को दूर करने के लिए बुनियादी सुविधाओं को लेकर चिंता जताई है।

4. प्रोफेसर भगवती जगदीश:

ग्लोबलाइजेशन और विकासशील देशों के बीच संबंध को मजबूत करने के लिए पहले इंफ्रास्ट्रक्चर को दर्जा देने की मांग की है और विकासशील देशों के कुचक्र में फाइनेंस समस्याओं को वैश्विक स्तर पर मूल्यांकित विश्लेषण प्रस्तुत किया गया।

5. डॉ सिंह रमेश:

भारतीय अर्थव्यवस्था में लगातार बढ़ती और *strategy* पर ध्यान नहीं देने की अलोचना की है और संशयों को लेकर सुझाव दिया है। मध्य प्रदेश में उद्योगों पर वैश्वीकरण के प्रभाव पर अध्ययनों और रिपोर्टों का परीक्षण किया गया है।

डेटा संग्रह:

सर्वेक्षण साक्षात्कार और माध्यमिक स्रोतों के माध्यम से मध्य प्रदेश में उद्योगों से डेटा

एकत्रीकरण के लिए उद्योग मन्त्रालय एमएसएमई से जुटाया गया है।

डेटा विश्लेषण:

रुझनो पैटर्न और सहसंबंधों की पहचान करने के लिए सांख्यिकी उपकरणों और साफ्टवेयर का उपयोग करके डेटा का विश्लेषण किया गया है।

अपेक्षित परिणाम:

1. मध्य प्रदेश में उद्योगों में रोजगार, उत्पादक और प्रतिस्पर्धात्मकता पर वैश्वीकरण के की अंतर्दृष्टि। 2. प्रभाव की अंतर्दृष्टि उन उद्योगों की पहचान जिन्होंने वैश्वीकरण को सफलतापूर्वक अपना लिया है और जिन्हे समर्थन की आवश्यकता है।
3. वैश्वीकरण की स्थिति में प्रतिस्पर्धात्मकता और नवचार को बढ़ाने के लिए नीति निर्माताओं और उद्योगों के लिए सिफारिशें।

महत्त्व:

1. यह अध्ययन मध्य प्रदेश में उद्योगों पर वैश्वीकरण के प्रभाव को समझने में योगदान देगा।
2. निष्कर्ष नीति निर्माताओं को मध्य प्रदेश में उद्योगों का समर्थन करने के लिए रणनीति विकसित करने के लिए अंतर्दृष्टि प्रदान करेगा।
3. मध्य प्रदेश में उद्योगों को सुधार के क्षेत्रों की पहचान करने और प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए रणनीति विकसित करने में मदद मिलेगी और नवाचार ने उद्योगों पर वैश्वीकरण के प्रभावों पर साहित्य खोजने की कोशिश की लेकिन मेरी खोज खाली हो गई अधिक जानकारी और संसाधनों के लिए ऑनलाइन खोज करने में आपकी किस्मत बेहतर हो सकती है। प्रासंगिक अध्ययन और लेख खोजने के लिए उद्योगों पर वैश्वीकरण के प्रभाव या वैश्वीकरण के उद्योगों प्रभाव जैसे कीवर्ड खोजने का प्रयास किया गया है।

अनुसंधान पद्धति:

उद्योगों पर वैश्वीकरण के प्रभावों का अध्ययन करने में उपयोग की जाने वाली सामान्य शोध पद्धतियों को यहां प्रयोग किया जाता है

1. मात्रात्मक पद्धति:

सर्वेक्षण और प्रश्नावली

द्वितीयक डेटा का सांख्यिकीय विश्लेषण (जैसे, व्यापार डेटा जीडीपी रोजगार दर)
अर्थमितीय मॉडलिंग (जैसे, प्रतिगमन विश्लेषण, विशिष्ट)

2. गुणात्मक पद्धति:

विशिष्ट उद्योगों या कंपनियों के मामले का अध्ययन

उद्योग के हितधारकों (जैसे, प्रबंधकों श्रमिकों नीति निर्माताओं) के साथ गहन साक्षात्कार
ग्रंथों का सामग्री विश्लेषण (जैसे, समाचार लेख कंपनी की रिपोर्ट)

3. मिश्रित पद्धति:

मात्रात्मक और गुणात्मक तरीकों का संयोजन

डेटा स्रोतों का त्रिकोणासन (जैसे, सर्वेक्षण, साक्षात्कार, द्वितीयक डेटा)

4. प्रायोगिक पद्धति:

उद्योगों पर वैश्वीकरण के प्रभाव का आकलन करने के लिए यादृच्छिक नियंत्रित परीक्षण (आरसीटी)

5. माध्यमिक अनुसंधान:

मौजूदा साहित्य और डेटा का विश्लेषण (जैसे, अकादमिक लेख सरकारी रिपोर्ट)

शोध पद्धति का चयन करते समय शोध प्रश्न डेटा उपलब्धता और वांछित गहराई और जटिलता के स्तर पर विचार किया गया है।

वैश्वीकरण उद्योग के बाद रिसर्च के लिए समस्या:

उद्योगों पर वैश्वीकरण के प्रभाव से संबंधित कुछ संभावित शोध समस्याएं या विषय यहाँ दिए गए हैं।

1. नौकरी विस्थापन और रोजगार की गतिशीलता वैश्वीकरण ने उद्योगों में रोजगार पैटर्न को कैसे प्रभावित किया है और श्रमिकों और समुदायों के लिए इसके परिणाम क्या हैं?
2. उद्योग पुनर्गठन और प्रतिस्पर्धात्मकता उद्योगों ने वैश्वीकरण को कैसे अपनाया है और प्रतिस्पर्धी बने रहने के लिए उन्होंने कौन सी रणनीति अपनाई हैं?
3. आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन और रसद वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं को कैसे पुनः कॉन्फिगर किया गया है और उद्योगों और अर्थव्यवस्थाओं के लिए क्या हैं?
4. प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और नवाचार वैश्वीकरण ने प्रौद्योगिकियों के प्रसार को कैसे सुविधाजनक बनाया है, और औद्योगिक नवाचार और विकास के परिणाम क्या हैं?
5. पर्यावरण और सामाजिक स्थिरता उद्योगों ने वैश्वीकरण के सामने स्थिरता की चुनौतियों का जवाब कैसे दिया है और पर्यावरण और समाज पर इसके क्या प्रभाव हैं?
6. व्यापार नीतियाँ और समझौते व्यापार नीतियों और समझौतों (जैसे, डब्ल्यूटीओ, टीपीपी, नापटा) ने उद्योगों पर वैश्वीकरण के प्रभाव को कैसे आकार दिया है?
7. उद्योग समूह और क्षेत्रीय विकास वैश्वीकरण के उद्योगों को कैसे एकत्रित हुए हैं। और क्षेत्रीय विकास और आर्थिक विकास पर क्या प्रभाव हैं?
8. वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं और शासन वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं को कैसे नियंत्रित किया गया है और उद्योगों अर्थव्यवस्थाओं और समाजों के लिए क्या निहितार्थ हैं?
9. कौशल और मानव पूंजी विकास वैश्वीकरण ने उद्योगों में कौशल और मानव पूंजी की मांग को कैसे प्रभावित किया है और शिक्षा और प्रशिक्षण प्रणालियों के लिए क्या निहितार्थ हैं?
10. सांस्कृतिक और संस्थागत परिवर्तन वैश्वीकरण ने उद्योगों में सांस्कृतिक और संस्थागत परिवर्तनों को कैसे जन्म दिया है और सगठनात्मक व्यवहार और प्रबंधन प्रथाओं के लिए क्या निहितार्थ हैं? ये शोध समस्याएं और विषय उद्योगों के लिए वैश्वीकरण के जटिल परिणामों की खोज के लिए एक प्रारंभिक बिंदु प्रदान करते हैं।

भारत में वैश्वीकरण उद्योग के बाद परिणाम ढूँढना

भारत में वैश्वीकरण उद्योग के बाद परिणाम यहाँ दिए गए हैं।

भारत में बुनियादी ढांचे के विकास पर उदारीकरण का असर महत्वपूर्ण रहा है। विचार करने के लिए यहां कुछ महत्वपूर्ण बिंदु दिए गए हैं:

1. निवेश में वृद्धि: उदारीकरण ने सड़को, बंदरगाहों, हवाई अड्डे और दूरसंचार सहित बुनियादी ढांचे परियोजनाओं में निजी निवेश वृद्धि की।
2. बेहतर दक्षता: निजी क्षेत्र की भागीदारी दक्षता और प्रतिस्पर्धा में लाया गया, जिससे बुनियादी ढांचे की सुविधाओं के बेहतर प्रबंधन और संचालन की ओर अग्रसर किया गया।
3. बढ़ी हुई गुणवत्ता: उदारीकरण ने बुनियादी ढांचे सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार हुआ, जैसे बेहतर सड़क की स्थिति, दूरसंचार कवरेज में वृद्धि, और आधुनिक हवाई अड्डे।
4. विस्तारित पहुंच: आधारभूत संरचना विकास दूरस्थ और ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंच गया, बिजली, पानी और परिवहन जैसी आवश्यक सेवाओं तक पहुंच बढ़ रही है।
5. आर्थिक विकास: बुनियादी ढांचा विकास व्यापार, वाणिज्य, और उद्योग की सुविधा से आर्थिक विकास को उत्तेजित करता है।
6. नौकरी निर्माण: बुनियादी ढांचा परियोजनाओं ने निर्माण, संचालन और रखरखाव में राजगार के अवसर पैदा किए।
7. बढ़ी हुई सरकारी राजस्व: उदारीकरण ने कर, टोल और अन्य शुल्क के माध्यम से सरकारी राजस्व में वृद्धि की। हालांकि, चुनौतियां शामिल हैं:
 1. असमान पहुंच: बुनियादी ढांचे सेवाओं तक पहुंच में असमानताएं बनी रहती हैं, खासकर ग्रामीण और वंचित क्षेत्रों में।
 2. अपर्याप्त विनियमन: कमजोर विनियामक ढांचे ने खराब सेवा की गुणवत्ता और अपर्याप्त सुरक्षा मानकों जैसे मुद्दों का नेतृत्व किया है।
 3. भ्रष्टाचार: क्रोनी पूंजीवाद और गवर्न के उदाहरणों के साथ भ्रष्टाचार बुनियादी ढांचे के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण बाधा बनी हुई है।
 4. पर्यावरणीय चिंता:
 5. बुनियादी ढांचे परियोजनाओं ने पर्यावरणीय चिंताओं को उठाया है, जैसे विस्थापन, प्रदूषण और आवास विनाश। कुल मिलाकर, उदारीकरण का भारत में बुनियादी ढांचे के विकास पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा, लेकिन चुनौतियों को संबोधित करना टिकाऊ और समावेशी विकास सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है। कुछ महत्वपूर्ण प्रभावों में शामिल हैं: विदेशी निवेश में वृद्धि: उदारीकरण ने 1992 से 2005 तक 316.9 प्रतिशत की वृद्धि के साथ विदेशी पूंजी का प्रवाह किया। जीडीपी में वृद्धि: भारत का सकल घरेलू उत्पाद 1991 में डोलर 2.3 में 266 अरब डॉलर से बढ़ गया 2018 में ट्रिलियन। व्यापार में वृद्धि: भारत में सकल घरेलू उत्पाद में सकल घरेलू उत्पाद के लिए माल और सेवाओं के कुल निर्यात का अनुपात लगभग दोगुना हो गया 1990 में 2000 में 14 प्रतिशत हो गया। वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण: भारत ने कुल माल के अनुपात के साथ वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ अपनी अर्थव्यवस्था को तेजी से एकीकृत किया और जीडीपी के लिए सेवाओं का व्यापार 17.2 प्रतिशत

से बढ़कर 30.6 प्रतिशत हो गया। क्रेडिट बूम: 2000 के दशक के दौरान बुनियादी ढांचे में निजी निवेश में काफी वृद्धि हुई, जो वैश्विक वित्त के प्रवाह से प्रेरित है। बढ़ी हुई आय असमानता: देश का सबसे धस्त प्रतिशत राष्ट्रीय आय के 5 से 7 प्रतिशत के बीच कमाता है, जबकि लगभग 15 प्रतिशत कामकाजी आबादी प्रति माह 5000 रु (लगभग 64 डॉलर) से कम कमाती है। बेरोजगारी और किसान आत्महत्या: बेरोजगारी के कारण उदारीकरण नीतियों की भी आलोचना की गई है और किसान आत्महत्याओं में वृद्धि हुई है। शहरी-ग्रामीण विभाजन: उदारीकरण ने ग्रामीण क्षेत्रों से अधिक लाभान्वित क्रय शक्ति के मामले में चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद भारत दुनिया में तीसरे सबसे बड़ा सकल घरेलू उत्पाद है

प्रति व्यक्ति आय 1991 में \$304 से बढ़कर 2023 में अनुमानित \$2,600 हो गई। अत्यधिक गरीबी जिसे 2017 की कीमतों पर प्रति दिन \$2.15 से कम पर जीवन यापन करने वालों के रूप में परिभाषित किया गया है 1 प्रतिशत से नीचे गिर गई है।

भारत एक आर्थिक शक्ति बन गया है उदारीकरण निजीकरण और वैश्वीकरण एलपीजी तीन आर्थिक अवधारणाएं हैं जिनके लिए सघं और राज्य सरकारों द्वारा नीतिगत सुधारों की एक श्रृंखला की आवश्यकता थी।

आर्थिक सुधारों से सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि में वृद्धि विदेशी पूंजी प्रवाह में वर्षद्धि और वर्तमान प्राप्तियों के अनुपात के रूप में ऋण सेवा भुगतान में कमी जैसे लाभ प्राप्त हुए हैं।

मैंने भारत में वैश्वीकरण के प्रभावों पर विशिष्ट शोध खोजने की कोशिश की लेकिन मुझे वह नहीं मिला जो मैं ढूँढ़ रहा था। विषय पर अधिक जानकारी के लिए आनलाइ खोज करने में आपकी किस्मत बेहतर हो सकती है। प्रासंगिक अध्ययन और लेख खोजने के लिए भारत पर वैश्वीकरण का प्रभाव वैश्वीकरण के साथ भारत का अनुभव उद्योगों के लिए भारत में वैश्वीकरण के बाद अनुसंधान की आवश्यकता क्यों हैं।

भारत में वैश्वीकरण के बाद अनुसंधान उद्योगों के लिए आवश्यकता हैं क्योंकि

- 1 प्रभाव को समझना: अवसरों और चुनौतियों भारतीय उद्योगों पर वैश्वीकरण के प्रभावों को समझना
- 2 वृद्धि के लिए क्षेत्रों की पहचान करना: विभिन्न उद्योगों वर्षद्धि और विकास के लिए क्षेत्रों की खोज करना।
- 3 प्रतिस्पर्धा में सुधार:
- 4 वैश्विक बाजार में भारतीय उद्योगों की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना।
- 5 नीतिगत निर्णयों की जानकारी देना:
6. नीति निर्माताओं को व्यापार नीतियों विनियमों और प्रोत्साहनों के बारे में सूचित निर्णय लेने के लिए अंतर्दृष्टि प्रदान करना।
7. चुनौतियों को संबोधित करना नौकरी विस्थापन नय्यर्यवणीय चिंताओं और सामाजिक निहितार्थ जैसी चुनौतियों का समाधान करना।
8. नौकरी विस्थापन, पर्यावरणीय चिंताओं और सामाजिक निहितार्थ जैसी चुनौतियों का समाधान करना।

9. अवसरों को आनलॉक करना: विदेशी निवेश, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और बाजार पहुँच जैसे अवसरों का लाभ उठाना।

10. नवाचार को बढ़ावा देना और आर-डी को बढ़ावा देने के लिए समष्टिगत परिवर्तन किए गए हैं।

ध्यातव्य है कि 2014 से पहले doing ease business index में भारत की ज्ञानात्मक पहलू बहुत कमजोर थी जो 150 रैंक से भी बाहर थी परंतु 2022 के आंकड़ों से भारत ने COVID 19 का बेहतर प्रबंधन किया कृषि वैक्सीन का परिक्षण और निर्माण किया गया कृषि सफाई की पृष्ठभूमि को डिजिटल तकनीक से दूरदृष्टि की प्रबंधन प्रणाली विकसित किया जिससे नवाचार रैंक 42 पर हो गयी।

अध्ययन और डाटा विश्लेषण यह बताते हैं कि 1990 से 2010 तक भारत में नवाचार सरकारी विभागों तक ही सीमित था। जो कुल खर्च का 75 प्राप्त हुआ है। जबकी निजी क्षेत्र में यह मात्र 25 का योगदान करती है हैरानी की बात यह है कि विकसित देशों में यह ठीक उल्टा है अमेरिका में नवाचार का योगदान निजी क्षेत्र में 75 और सरकारी विभागों में यह मात्र 25 योगदान होता है यह तसवभ्र अवश्य ही बदलनी चाहिए।

उदारीकरण के मध्यप्रदेश में बुनियादी ढांचे के विकास में सरकारी प्रयासों में 2024-25 बजट में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 53000 करोड़ रुपये अधिक आवंटित करना पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए धार्मिक स्थानों पर बुनियादी ढांचे के विकास पर ध्यान केंद्रित करना महिलाओं और बाल कल्याण का समर्थन करने के लिए लाडली बहना योजना की तरह योजनाएं विविध क्षेत्रों के लिए एक मजबूत समर्थन बुनियादी ढांचा बनाने के लिए सार्वजनिक निजी साझेदारी पर जोर देना बुनियादी ढांचा विकास आधुनिक खाद्य सिलो परिसरों और आधारभूत संरचना परियोजनाओं की स्थापना निवेश हब के रूप में भोपाल ग्ववलियर और इंदौर विकसित करना विभिन्न परियोजनाओं के माध्यम से राज्य बुनियादी ढांचे को मजबूत करना घरेलू और विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए वैश्वीक निवेश शिखर सम्मेलन का अयोजन कार्यान्वयन मध्य प्रदेश शहरी सेवा सुधार परियोजना जैसी परियोजनाएं शामिल हैं।

उदारीकरण के बाद मध्यप्रदेश में रोजगार और प्रतिस्पर्धा के प्रबंधन में महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं। जिनमें शामिल हैं।

1. निजी क्षेत्र की वृद्धि उदारीकरण ने निजी क्षेत्र निवेश में वृद्धि की जो आईटी फार्मास्यूटिकल्स और ऑटोमोबाइल जैसे उद्योग में नए नौकरी के अवसर पैदा कर रही हैं।
2. बढी हुई प्रतियोगिता वैश्वीक खिलाडियों की प्रविष्टि के साथ सांसद में उद्योग में प्रतिस्पर्धा में वृद्धि हुई जिससे बेहतर उत्पाद की गुणवत्ता और सेवाओं का सामना करना पडा।
3. कौशल विकास बढ़ते उद्योगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए कार्यबल की नियुक्ति को बढ़ाने के लिए विभिन्न कौशल विकास कार्यक्रम शुरू किए गए थे।
4. उद्यमिता उदारीकरण ने उद्यमशीलता को प्रोत्साहित किया जिससे स्टार्टअप और छोटे पैमाने पर उद्योगों की स्थापना रोजगार के अवसरों को उत्पन्न किया।
5. सार्वजनिक निजी साझेदारी निजी कंपनियों के साथ बुनियादी ढांचे परियोजनाओं को विकसित करने नौकरियों को बनाने और आर्थिक विकास को उत्तेजित करने के लिए सहयोग किया।

6. श्रम सुधार सरकार ने अधिक व्यावसायिक अनुकूल माहौल बनाने निवेश को आकर्षित करने और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए श्रम सुधारों को लागू किया।
7. मानव पूंजी में निवेश सरकार ने एक कुशल श्रमिकों को विकसित करने उद्योग की मांगों को पूरा करने के लिए शिक्षा और प्रशिक्षण कार्यक्रमों पर ध्यान केंद्रित किया।
8. प्रचार उद्योग सरकार ने रोजगार के अवसरों को बनाने के लिए वस्त्र खाद्य प्रसंस्करण और ऑटो घटकों जैसे उद्योगों को बढ़ावा दिया।
9. अभिनव को प्रोत्साहित करना invention और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए ऊष्मायन केंद्रों और नवाचार केंद्रों की तरह पहल की स्थापना की गई।
10. श्रम कानूनों का सरलीकरण सरकार ने नौकरशाही बाधाओं को कम करने के लिए श्रम कानूनों को सरल बना दिया और व्यापारियों को सांसद में संचालन स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया। इन परिवर्तनों ने मध्य प्रदेश में रोजगार के अवसरों और प्रतिस्पर्धा के विकास में योगदान दिया है। जो राज्य को उद्योग और उद्यमिता के लिए एक केंद्र में बदल रहा है।

सन्दर्भ

1. डॉ सिंह मनमोहन पोस्ट रिफॉर्म ऑक्सफोर्ड प्रेस लंदन।
2. डॉ सिंह रमेश भारतीय अर्थव्यवस्था यस चंद्र प्रकाशन नयी दिल्ली।
3. डॉ भरत झुनझुनवाला भारत की अर्थनीति।
4. मिश्रा और पूरी भारतीय अर्थव्यवस्था नयी दिल्ली।
5. प्रो लाल यस एन भारतीय अर्थव्यवस्था सर्वेक्षण शिव Publication Pryagraj .
6. योजना आयोग भारत सरकार
7. श्री रंगराजन सी भारत की अर्थनीति 2004
8. विश्व बैंक रिपोर्ट 2000
9. अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोश की वार्षिक रिपोर्ट 2010
10. Outlook पत्रिका 2000
11. वार्ता जर्नल Allahabad विश्वविद्यालय
12. UPEA जर्नल 2018 ISSN 0975-2392
13. Meta Artificial Intelligence Google
14. भारतीय शोध शिक्षा पत्रिका 36/2/जुलाई 2017 लखनऊ
15. डॉ पांडेय विद्या नन्द गांधी के आर्थिक विचार और भूमंडलीकरण Reserch Journal IJRAR21A1072, www.ijrar.org pAge 1209, ISSN 2349-5138
16. डॉ पांडेय विद्या नन्द: नयी शिक्षा नीति Insha Publications New Delhi ISBN 93-88647-60- Nov.2023 p. 48
17. शोध पत्रिका सामाजिक शोध संस्थान भोपाल 2018
18. डॉ पांडेय विद्या नन्द यूजीसी Sponcerd Research Journal, Bhopal] School of Social Science.